

13.18 hrs.

## ESTIMATES COMMITTEE

## Hundred and Thirteen Report

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada) : Sir, I beg to present the Hundred and Thirteen Report of the Estimates Committee regarding action taken by Government on the recommendations contained in their Fifty-Third Report on the erstwhile Ministry of Education (now Ministry of Education and Youth Services)—Indian School of International Studies, New Delhi.

SHRI NATH PAI (Rajapur) : I did not get a reply regarding my Calling-Attention Motion. The Governor of West Bengal has written to the various parties asking them to show cause why another Government should not be formed, "why did you not support the Government" and all that. He has absolutely no power and this is a very serious constitutional matter. The Governor is acting *ultra vires* of the Constitution.

MR. SPEAKER : I am seeing that.

SHRI NATH PAI : Under what authority the Governor wrote that letter, I would like to know.

MR. SPEAKER : I got it very late. I could not see that when I was coming here.

श्री मधु लिमये (मुं गेर) : अध्यक्ष महोदय, ... (ब्यवधान)...

SHRI MANUBHAI PATEL (Dabhoi) : The hon. Member, Shri Kashinath Pandey has been assaulted and we wanted some information on that.

MR. SPEAKER : I am sending that to the Home Minister. (*Interruption*) About Shri Kashinath Pandey, I am sending it to the Home Minister and I will let you know. (*Interruption*)

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : The transport system in Delhi has come to a standstill. The Taxis and scooters are on strike; Members could not

come to the House : it is a very serious matter.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, ... (ब्यवधान)...

SHRI JYOTIRMOY BASU : Because of the strike, we cannot move and come to the House (*Interruption*) For the past two days, we are without any transport.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : बंगाल में क्या हुआ ?... (ब्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मधु लिमये जी, आप बोलते क्यों नहीं हैं ।

श्री मधु लिमये : मैं तो खड़ा हुआ हूँ ।... (ब्यवधान)...

SHRI RAM KISHAN GUPTA (Hissar) : I have given notice about the serious matter and I requested my Calling Attention to be taken up. Shri Jagjivan Ram has stayed in Raj Bhavan and he is doing so many things. I requested that my Calling Attention must be admitted.

13.19 hrs.

## MATTER UNDER RULE 377

## Industrial Licencing Policy

श्री मधु लिमये (मुं गेर) : अध्यक्ष महोदय, उद्योग मन्त्री के द्वारा लाइसेंसिंग के बारे में जिस नयी नीति की घोषणा की गई है उसका सवाल में यहां पर उठाना चाहता हूँ ।... (ब्यवधान)...

AN HON. MEMBER : It can be raised after lunch hour.

श्री मधु लिमये : वा तो स्पष्ट कर दीजिये या मुझे चलने दीजिये ।

MR. SPEAKER : About the point mentioned by you, Shri Shiva Chandra Jha we should postpone it after the lunch. I enquired about your question, Mr. Madhu

Limaye and Mr. Nath Pai, why it was not clubbed with the other Short Notice Question. I have got a copy of that. That relates to Islamabad. This question is about the labour situation. That was the difficulty about it.

Now, we adjourn for lunch and meet again at 2-25 P.M.

13.20 hrs.

*The Lok Sabha Adjourned for Lunch till Twenty-five minutes past Fourteen of the Clock.*

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Twenty-seven minutes past Fourteen of the Clock.*

[Mr. Speaker in the Chair.]

MATTER UNDER RULE 377—Contd.

Industrial Licencing Policy—Contd.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, उद्योग मन्त्री द्वारा जिस नई लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की गई है उसके बारे में मेरी कुछ आपत्तियाँ और आक्षेप हैं। इस तरह की आपत्तियाँ पहले भी हम लोग यहाँ पर उठा चुके हैं, लेकिन मन्त्री महोदय अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, उनकी आदतें नहीं सुधरतीं, जब भी उन्हें नीति के बारे में कोई घोषणा करनी होती है...

एक माननीय सदस्य : यह क्या लंग्वेज है ?

श्री मधु लिमये : मैंने किसी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। मैंने केवल यह कहा कि यह न तो अपनी आदतें बदलते हैं और न अपनी हरकतों से बाज आते हैं। इसमें क्या असंसदीय भाषा है ?

उन्हें कह रहा था कि जब कभी मन्त्री महोदय को नीतियों के सम्बन्ध में कोई घोषणा करनी हो तो उन्हें चाहिए कि वह इस सदन

के सामने आकर सदन को विश्वास में लेकर नई नीतियों का ऐलान करें।

मन्त्री महोदय को याद होगा कि जब दत्त कमेटी की रिपोर्ट आई तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पर सदन में बहस होगी और बहस में जो मुद्दे उपस्थित किये जायेंगे उन पर सरकार साबेगी तथा बाद में नई नीति का ऐलान करेगी। लेकिन दत्त कमेटी की रिपोर्ट पर पिछले सत्र में बहस नहीं हो पाई। कम से कम इस सत्र के प्रारम्भ में उनको खुद इस बहस को रखवाना चाहिए था। लेकिन वह भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इस सत्र के प्रारम्भ होने के दो एक दिन पहले नई नीति का ऐलान किया और उसके बाद उस नीति के विषय को स्पष्ट करने के लिए शायद पिछली 14 तारीख को, यानि 14 मार्च को उन्होंने एक वक्तव्य दिया। असल में इस सदन को कोई मौका नहीं मिल रहा है कि उद्योग मन्त्रालय की जो नीतियाँ हैं उनके बारे में वह अपनी राय व्यक्त करे।

यह बार-बार कहते हैं कि हम पूँजी का और आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण नहीं चाहते हैं, समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जिन मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को और नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था को पैदा किया है वह न छोड़ा है और न गंवा है। वह क्या चीज है यह वही जानें।

एक माननीय सदस्य : खच्चर।

श्री मधु लिमये : खच्चर का भी उपयोग होता है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं। नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था के कारण न केवल सत्ता का और पूँजी का केन्द्रीयकरण हो रहा है बल्कि ऐसे उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जाता है जो हमेशा सरकार का समर्थन करते हैं, सरकार को पैसा देते हैं, सरकार का दख्खार करते हैं और सरकार की खुशामद करते हैं। क्या मदन को इस बात का पता नहीं है कि उन लोगों की